

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग
संख्या 1331 / वित्त अनुभाग-5 / 2003
देहरादून: दिनांक 31 अक्टूबर, 2003

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- उत्तरांचल शासन के विभिन्न विभागों, राजकीय निगमों / उपक्रमों के आपसी विवादों के निराकरण हेतु सचिव समिति का गठन।

शासन के विभिन्न विभागों राजकीय निगमों एवं उपक्रमों के मध्य समय समय पर आपसी विवाद होते रहते हैं। अधिकांश विवाद राजस्व देयों, व्यापार कर, विद्युत, एक्साईज आदि की समस्याओं को लेकर उत्पन्न होती हैं, जिनके निराकरण हेतु सम्बन्धित विभागों / निगमों / उपक्रमों द्वारा न्यायालय / न्याय अधिकरण के समक्ष वाद प्रस्तुत किये जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया से एक ओर विभिन्न विभागों / उपक्रमों की कार्यप्रणाली एवं उपलब्धियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वहीं न्यायालय के समक्ष विवादों के प्रस्तुत किये जाने से इन विवादों के न्यायालयों में होने वाले व्यय को सम्बन्धित विभाग द्वारा भुगतान करना पड़ता है जिसका भार अन्ततः शासन पर ही पड़ता है। इसके साथ ही साथ विवादों के निस्तारण में काफी विलम्ब होता है जो शासन के विभिन्न विभागों / निगमों एवं उपक्रमों के हित में नहीं है।

इस संबंध में अविभाजित उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या-160 / 7-न्याय-4-9 / 91 दिनांक 16-1-1991 द्वारा राज्य सरकार के एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग के विरुद्ध अथवा राजकीय निगम या राजकीय उपक्रमों के विरुद्ध वाद / अपील दायर करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

उक्त समस्या के निराकरण हेतु राज्य के विभिन्न विभागों एवं राजकीय निगमों / उपक्रमों के मध्य में उत्पन्न होने वाले विवादों के निस्तारण के लिये निम्न रूप से सचिव समिति का गठन किया जाता है:-

- 1-प्रमुख सचिव / सचिव वित्त, उत्तरांचल शासन
- 2-प्रमुख सचिव / सचिव उद्योग, उत्तरांचल शासन
- 3- सचिव, न्याय, उत्तरांचल शासन
- 4- प्रमुख सचिव / सचिव सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग,

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य

यह निर्देशित किया जाता है कि शासकीय विभागों / राजकीय निगमों / उपक्रमों द्वारा आपसी विवादों को उक्त समिति को सन्दर्भित किये जाने की स्थिति में समिति के अध्यक्ष समिति की बैठक बुला कर सन्दर्भित विवादों का निराकरण / निस्तारण करेंगे।

किसी भी शासकीय विभाग, राज्य के उपक्रम व राज्य के निगम द्वारा उक्त समिति को अभिनिर्णय के विरुद्ध पुनः किसी सक्षम न्यायालय में विवाद/ मामला नहीं ले जाया जायेगा।

सम्बन्धित समिति के अभिनिर्णय से किसी शासकीय विभाग राजकीय निगम/ उपक्रम, के सन्तुष्ट न होने की दशा में सम्बन्धित शासकीय विभाग/ राज्यकीय निगम/ उपक्रम/ मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रकरण को प्रस्तुत कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद का अथवा यदि मंत्रिपरिषद द्वारा कोई समिति गठित की जाती है तो ऐसी समिति का निर्णय अंतिम होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे, इस सन्दर्भ में पूर्व में किये गये आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

(आर० एस० टोलिया)

मुख्य सचिव,
उत्तरांचल शासन।

संख्या (1)/वित्त अनुभाग-5/ 2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 2- समास्त विभागाध्यक्ष, उत्तरांचल।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
- 4- अध्यक्ष, व्यापार कर अधिकरण, देहरादून।
- 5- प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य अधिकारी राजकीय निगम/ उपक्रम उत्तरांचल।

(इन्दु कुमार पाण्डे)

प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।